

प्रेषक,

डी०एस० गब्र्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 11 जुलाई, 2016

विषय:- जनपद चम्पावत में राजस्व विभाग की कुल 25 नाली 15 मुट्ठी भूमि पर्यटन विभाग को तथा इसके स्थान पर तहसील कार्यालय एवं अन्य हेतु कुमाऊं मण्डल विकास निगम की कुल 28 नाली भूमि राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2218 एवं 2219/सात-उ०पर्य०अव०वि०नि०का०-भू० हस्ता०/2014-15 दि०-25.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम, पटवारी क्षेत्र, तहसील एवं जनपद चम्पावत के गैर ज०वि० श्रेणी-1(क) के खतौनी खाता सं०-313 मध्ये खसरा सं०-3310 से 3339 तक, 3339 से 3356 तक, 3358 से 3361 तक तथा 3363 से 3365 तक कुल 53 खेतों की तथा श्रेणी-6(1) अकृषक भूमि के खतौनी खाता सं०-319 के कुल 10 खेतों की यथा प्रस्तावित कुल 25 नाली 15 मुट्ठी (0.519 है०) भूमि जो राजस्व विभाग के नाम दर्ज अभिलेख है, को पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को तथा पर्यटन विभाग को हस्तांतरित किये जाने पर तहसील कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों को अन्यत्र स्थापित किये जाने हेतु उक्त भूमि के बदले में कुमाऊं मण्डल विकास निगम लि० के नाम दर्ज एवं उसके स्वामित्व की ग्राम खर्ककाकी, पटवारी क्षेत्र मुडियाना, तहसील एवं जनपद चम्पावत के खतौनी खाता सं०-187 के खसरा सं०-4501, खाता सं०-168 के खसरा सं०-45बी, 421, 5384, 5387, 5389, खाता सं०-160 के खसरा सं०-4908, 4921, खाता सं०-164 के खसरा सं०-4910, 4911, 4913, 4912, खाता सं०-177 के खसरा सं०-4922, 4924, 4927, 4938, 4939, खाता सं०-206 के खसरा सं०-4928, 4929, 4930, 4946, खाता सं०-6 के खसरा सं०-4931, 4933, 4934, 4936, खाता सं०-35 के खसरा सं०-4941, 4942, खाता सं०-182 के खसरा सं०-4947 तथा खाता सं०-116 के खसरा सं०-4948 की यथा प्रस्तावित कुल 28 नाली भूमि, श्रेणी-1(क) की राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश सं०-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दि०-15.02.2002 के प्राविधानों के अधीन तथा पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की विभागीय सहमति के दृष्टिगत प्रस्तावित कुल 28 नाली भूमि राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित की जाती है तथा प्रस्तावित कुल 25 नाली 15 मुट्ठी भूमि पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 8- प्रश्नगत जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0-436/2011/SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0-जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पू0प0संख्या- 654 /XVIII(II)/2016-18(24)/2016 समदिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
- 4- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।